पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2019 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.17804
में

2022 की लेटर्स पेटेंट अपील सं.525

मो. शमशाद आलम, पिता- स्वर्गीय महमूद आलम, निवासी - मोहल्ला- महमूद खान
टोला, थाना- के. हाट, जिला- पूर्णिया

.....अपीलकर्ता/ओ

बनाम

1. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. पुलिस महानिदेशक, बिहार सरकार, पटना।
3. जिला दंडाधिकारी, पूर्णिया।
4. उपायुक्त (प्रतिष्ठान), पूर्णिया।

.....प्रतिवादी/ओ

उपस्थिति:

अपीलार्थी/ओं के लिए: श्री शहाबुद्दीन अजीम @ एस. अजीम, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए: श्री सरोज कुमार शर्मा, ए.ए.जी-3 के ए.सी.

=====

संछिप्त मामला: यह मामला इस बात की पुष्टि करता है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति एक निहित अधिकार नहीं है, बल्कि सरकारी नीतियों के तहत प्रदान की गई रियायत है। माननीय उच्च न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को बरकरार रखते हुए अपील को खारिज कर दिया कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति उचित समय के भीतर मांगी जानी चाहिए और आवेदन के समय वित्तीय संकट एक महत्वपूर्ण कारक है। फ़ैसले में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि एक ही राहत के लिए बार-बार मुकदमा दायर करने की अनुमति नहीं है।

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति - अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पाने का अधिकार अनिश्चित काल तक नहीं बढ़ता है, और यदि कोई परिवार वित्तीय संकट के बिना वर्षों तक जीवित रहा है, तो दावा वैधता खो देता है। अपीलकर्ता के पिता, जो पूर्णिया के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दफ्तरी थे, की 1991 में सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी। अपीलकर्ता उस समय नाबालिग था और उसने वयस्क होने के बाद 1999 में ही अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था (पैरा 2)।

निर्णय- अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति एक निहित अधिकार नहीं है अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने की सीमा अवधि - 1991 में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने की सीमा अवधि पांच वर्ष थी, जिसका अर्थ है कि नवीनतम संभावित आवेदन 1996 तक किया जाना चाहिए था (पैरा 6)

अपीलकर्ता ने केवल 1999 में आवेदन किया, जिससे पता चलता है कि परिवार वित्तीय संकट के बिना वर्षों तक खुद को बनाए रखने में कामयाब रहा। - निर्णय दिया गया, अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने में देरी यह दर्शाती है कि परिवार को तत्काल वित्तीय आवश्यकता नहीं है, जो कि योजना की मुख्य आवश्यकता है (पैरा 7)।

एक ही राहत के लिए बार-बार मुकदमा दायर करना जायज नहीं है - अपीलकर्ता ने पहले कई बार हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था - सीडब्ल्यूजेसी संख्या 15697/2011, 14.11.2013 को निर्देशों के साथ निपटाया गया - एमजेसी संख्या 4448/2014, एक अवमानना याचिका, 22.02.2018 को आगे चुनौती देने की स्वतंत्रता के साथ निपटाया गया - सीडब्ल्यूजेसी संख्या 17804/2019, 26.08.2022 को खारिज कर दिया गया (पैरा 2)।

विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एक ही राहत की मांग करने वाली लगातार रिट याचिकाएँ अस्वीकार्य हैं (पैरा 2)।

अनुकंपा नियुक्ति पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश - माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केनरा बैंक बनाम अजितकुमार जी.के. (2025) सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के मुख्य सिद्धांत - अनुकंपा नियुक्ति एक अपवाद है, अधिकार नहीं - नियमों या सरकारी आदेशों के बिना नहीं की जा सकती - कर्मचारी की मृत्यु के तुरंत बाद या उचित समय के भीतर आवेदन किया जाना चाहिए - विलंबित आवेदन से पता चलता है कि वित्तीय संकट मौजूद नहीं है। लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज किया गया - किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील दत्ता मिश्रा

मौखिक निर्णय

(द्वारा: माननीय श्री न्यायमूर्ति पी. बी. भजंत्री)

दिनांक: 03-03-2025

अपीलार्थी ने 2019 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 17804 में पारित दिनांक 26.08.2022 के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश पर आपत्ति जताई है।

2. अपीलार्थी के पिता, जो पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के कार्यालय में एक दफतरी थे, की मृत्यु दिनांक 29.12.1991 को सेवाकाल के दौरान हो गई थी। अपने पिता की मृत्यु की तारीख तक, वह नाबालिग थे और उनकी उम्र लगभग दस वर्ष थी। ज्ञात हुआ है कि उन्होंने वर्ष 1999 में वयस्क होने पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। तत्पश्चात, प्रतिवादियों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप वे मामले को आगे बढ़ाते रहे तथा अंततः उन्होंने 2011 की सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 15697 दायर करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसका 14.11.2013 को कुछ निर्देशों के साथ निपटारा कर दिया गया। 2011 की सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 15697 में पारित दिनांक 14.11.2013 के आदेश का पालन न करने के कारण अपीलकर्ता को 2014 की एम.जे.सी. संख्या 4448 के तहत अवमानना याचिका दायर करने के लिए बाध्य होना पड़ा तथा अपीलकर्ता को प्रतिवादियों की कार्रवाई पर आपत्ति करने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखते हुए 22.02.2018 को इसका निपटारा कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने 2019 की सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 17804 दायर की तथा इसका निपटारा 26.08.2022 को कुछ टिप्पणियों के साथ किया गया, जो निम्नानुसार है:

"यह न्यायालय यह मानता है कि कि याचिकाकर्ता को एक के बाद एक उसी राहत की मांग करने वाली रिट याचिकाएं दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो पहले की रिट कार्यवाही में दी गई थी। यदि किसी भी प्राधिकरण ने इस न्यायालय के पहले के निर्देश का पालन नहीं किया है, तो याचिकाकर्ता का उपाय पिछली कार्यवाही में पारित आदेश को लागू करने में निहित होगा, जिसमें रिकॉर्ड के अनुसार एमजेसी संख्या 4448/2014 लंबित है। अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि याचिकाकर्ता की पिछली रिट कार्यवाही के बाद अधिकारियों द्वारा कोई आदेश

पारित किया गया है, जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। रिट याचिका त्रुटिपूर्ण है और खारिज की जाती है।

"

3. विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 26.08.2022 के उपरोक्त आदेश से व्यथित महसूस करते हुए, उन्होंने 2022 की वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 525 दायर की है।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी की ओर से कोई गलती नहीं थी। अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने में राज्य सरकार की सामाजिक योजना के आलोक में उन्हें अनुकंपा नियुक्ति से वंचित कर दिया गया है। इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह टिप्पणी करने में त्रुटियां की हैं कि अपीलार्थी मुकदमे पर मुकदमा दायर कर रहा था। यह अपीलकर्ता का मौलिक अधिकार था कि जब भी वह आदेशों या किसी निर्णय से व्यथित होता है, तो उसे कुछ वैधानिक उपाय करने होते हैं और इसे 2019 की सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 17804 दायर करते समय लागू किया गया है।

5. संबंधित पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

6. अनुकंपा नियुक्ति कोई मौलिक अधिकार नहीं है और यह राज्य सरकार के नियमों या कार्यकारी आदेश के अनुसार शासित होती है। निःसंदेह, अनुकंपा नियुक्ति राज्य सरकार के सामाजिक कानून या सामाजिक योजना द्वारा शासित होती है जो 29.12.1991 को प्रचलन में थी, जिस तिथि को अपीलकर्ता के पिता की मृत्यु हुई थी, यह मानते हुए कि वर्ष 1991 में पांच वर्ष की सीमा अवधि थी, जो वर्ष 1996 में समाप्त हो गई है, जबकि अपीलकर्ता ने वर्ष 1999 में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दायर किया था। इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपीलकर्ता परिवार 1991 से 1999 तक कठिनाई में रहा, जिस तिथि को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार माना है कि अनुकंपा नियुक्ति की मांग के संबंध में कोई निहित अधिकार नहीं है। हाल ही में,

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केनरा बैंक बनाम अजितकुमार जी.के. के मामले में (2025 की दीवानी अपील संख्या 255, 2019 की एसएलपी (दीवानी) संख्या 30532 से उत्पन्न) 11.02.2025 को तय की गई है, जिसमें अनुकंपा नियुक्ति के लिए 26 मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं:-

"11. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की रूपरेखा पर इस न्यायालय के निर्णय बहुत हैं और हमारे लिए यह उचित होगा कि हम कुछ सुस्थापित सिद्धांतों पर विचार करें, जो कि पूर्व उदाहरणों के माध्यम से कानून के नियम में परिवर्तित हो गए हैं। वे (क्रमिक नहीं बल्कि प्रासंगिक क्रम में) हैं:

(क) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, जो मानवीय आधार पर दी जाती है, सार्वजनिक रोजगार के मामले में समानता के नियम का अपवाद है [जनरल मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम अंजू जैन (2008) 8 एससीसी 475 में रिपोर्ट की गई]।

(ख) नियमों या निर्देशों के अभाव में अनुकंपा नियुक्ति नहीं की जा सकती [हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड बनाम कृष्णा देवी (2002) 10 एससीसी 246 में रिपोर्ट की गई]।

(ग) अनुकंपा नियुक्ति आम तौर पर दो परिस्थितियों में दी जाती है, जो सामान्य नियम के अपवाद के रूप में बनाई गई हैं, अर्थात् परिवार में अचानक आने वाले संकट से निपटने के लिए, चाहे वह सेवा के दौरान कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के कारण हो या चिकित्सा दृष्टि से अक्षम होने के कारण हो [वी. शिवमूर्ति बनाम भारत संघ (2008) 13 एससीसी 730 में रिपोर्ट की गई]।

(घ) नियोक्ता द्वारा अनुकंपा आधार पर रोजगार देने का पूरा उद्देश्य मृतक या अक्षम कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को अचानक वित्तीय संकट से उबरने में सक्षम बनाना है, इसलिए संकट में फंसे परिवार को उबारने के लिए अनुकंपा आधार पर नियुक्तियां तुरंत की जानी चाहिए [सुषमा गोसाईं बनाम भारत संघ (1989) 4 एससीसी 468 में रिपोर्ट की गई]।

(ङ) चूंकि अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित नियम साइडडोर एंट्री की अनुमति देते हैं, इसलिए इसकी सख्त व्याख्या की जानी चाहिए [उत्तरांचल जल संस्थान बनाम लक्ष्मी देवी (2009) 11 एससीसी 453 में रिपोर्ट की गई]।

(च) अनुकंपा नियुक्ति एक रियायत है न कि अधिकार और नियमों में निर्धारित मानदंड सभी उम्मीदवारों द्वारा संतुष्ट होने चाहिए [सेल बनाम मधुसूदन दास (2008) 15 एससीसी 560 में रिपोर्ट की गई]

(छ) कोई भी व्यक्ति उत्तराधिकार के माध्यम से अनुकंपा नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता [छत्तीसगढ़ राज्य बनाम धीरजो कुमार सेंगर (2009) 13 एससीसी 600 में रिपोर्ट की गई]।

(ज) केवल वंश के आधार पर नियुक्ति हमारी संवैधानिक व्यवस्था के प्रतिकूल है, और अपवाद होने के कारण, इस व्यवस्था की व्याख्या सख्ती से की जानी चाहिए और इसे केवल उसी उद्देश्य तक सीमित रखा जाना चाहिए जिसे प्राप्त करना है [भवानी प्रसाद सोनकर बनाम भारत संघ (2011) 4 एससीसी 209 में रिपोर्ट की गई]।

(झ) संबंधित कर्मचारी (परिवार का एकमात्र कमाने वाला) की मृत्यु/चिकित्सा अक्षमता की स्थिति में कोई भी अनुकंपा नियुक्ति का दावा

नहीं कर सकता है, जैसे कि यह एक निहित अधिकार हो, और मृतक के परिवार की वित्तीय स्थिति पर विचार किए बिना कोई भी नियुक्ति कानूनी रूप से अस्वीकार्य है [यूनियन ऑफ इंडिया बनाम अमृता सिन्हा (2021) 20 एससीसी 695 में रिपोर्ट की गई]।

(ज) अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन मृत्यु/अक्षमता के तुरंत बाद और किसी भी मामले में उसके बाद उचित अवधि के भीतर किया जाना चाहिए अन्यथा यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मृतक/अक्षम कर्मचारी के परिवार को वित्तीय सहायता की तत्काल आवश्यकता नहीं है। ऐसी नियुक्ति एक निहित अधिकार नहीं है, इसलिए आवेदन करने का अधिकार भविष्य में किसी भी समय प्रयोग नहीं किया जा सकता है और समय बीतने और संकट खत्म होने के बाद भी इसे पेश नहीं किया जा सकता है [ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम अनिल बघाकर (2009) 13 एससीसी 112 में रिपोर्ट की गई]।

(ट) अनुकंपा रोजगार का उद्देश्य मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्य को मृतक द्वारा धारित पद के नीचे के पद देना नहीं है। मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना अनुकंपा आधारित रोजगार देना और श्रेणी III और IV से ऊपर के पदों पर अनुकंपा आधारित नियुक्ति करना कानूनी रूप से अनुचित है [उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य (1994) 4 एससीसी 138 में रिपोर्ट की गई]।

(ठ) मृतक कर्मचारी के आश्रितों की गरीबी मामले को अनुकंपा नियुक्ति की योजना के तहत लाने की पहली पूर्व शर्त है। यदि निर्धनता के तत्व और वित्तीय अभाव से राहत के लिए तत्काल सहायता प्रदान करने की आवश्यकता को अनुकंपा नियुक्ति से हटा दिया जाता है, तो यह सेवा में रहते हुए मरने

वाले कर्मचारी के आश्रितों के पक्ष में एक आरक्षण साबित होगा जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत समानता गारंटी के आदर्श के साथ सीधे टकराव में होगा [यूनियन ऑफ इंडिया बनाम बी. किशोर (2011) 13 एससीसी 131 में रिपोर्ट की गई]।

(ड) अनुकंपा नियुक्ति का विचार अंतहीन अनुकंपा प्रदान करना नहीं है [आई.जी. (कार्मिक) बनाम प्रहलाद मणि त्रिपाठी (2007) 6 एससीसी 162 में रिपोर्ट की गई]।

(ढ) यह संतुष्टि कि परिवार के सदस्य वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति उन्हें इस तरह के संकट से उबरने में मदद कर सकती है, पर्याप्त नहीं है; आश्रित को ऐसी नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा [गुजरात राज्य बनाम अरविंदकुमार टी. तिवारी (2012) 9 एससीसी 545 में रिपोर्ट की गई]।

(ण) किसी पद के लिए आरक्षण नहीं हो सकता तब तक जब तक आवेदक कई वर्षों के बाद वयस्क नहीं हो जाता, जब तक कि कुछ विशिष्ट प्रावधान न हों [संजय कुमार बनाम बिहार राज्य (2000) 7 एससीसी 192 में रिपोर्ट की गई]

(त) पारिवारिक पेंशन का अनुदान या सेवांत लाभों का भुगतान रोजगार सहायता प्रदान करने के विकल्प के रूप में नहीं माना जा सकता है। साथ ही, यह केवल दुर्लभ मामलों में ही होता है और वह भी यदि अनुकंपा नियुक्ति के लिए योजना द्वारा प्रदान किया जाता है और अन्यथा नहीं, यह कि एक आश्रित जो मृत्यु/अक्षमता की तिथि पर नाबालिग था, वयस्क होने पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है [केनरा बैंक (ऊपर)]।

(थ) कर्मचारी की मृत्यु/अक्षमता के कई वर्षों बाद या मृतक/अक्षम कर्मचारी के आश्रित के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर उचित विचार किए बिना अनुकंपा के आधार पर की गई नियुक्ति सीधे संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के विरुद्ध होगी [राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनाम नीरज कुमार सिंह (2007) 2 एससीसी 481 में रिपोर्ट की गई]

(द) आश्रितों को यदि लाभकारी रूप से नियोजित किया गया है तो उन पर विचार नहीं किया जा सकता है [हरियाणा लोक सेवा आयोग बनाम हरिंदर सिंह (1998) 5 एससीसी 452 में रिपोर्ट की गई]।

(ध) मृतक कर्मचारी के उत्तराधिकारियों को मिलने वाले सेवानिवृत्ति लाभों को यह निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए कि मृतक का परिवार गरीबी में है या नहीं। न्यायालय गरीबी के मानदंड को "बहुत संपन्न नहीं" में परिवर्तित नहीं कर सकता। [जनरल मैनेजर (डी और पीबी) बनाम कुंती तिवारी (2004) 7 एससीसी 271 में रिपोर्ट की गई]।

(न) मृतक कर्मचारी के परिवार की वित्तीय स्थिति, जो कथित रूप से संकट या दरिद्रता में है, का मूल्यांकन किया जाना चाहिए अन्यथा योजना का उद्देश्य विफल हो जाएगा क्योंकि ऐसी स्थिति में, मरने वाले कर्मचारी का कोई भी और हर आश्रित रोजगार का दावा करेगा जैसे कि सार्वजनिक रोजगार विरासत में मिला हो [यूनियन ऑफ इंडिया बनाम शशांक गोस्वामी (2012) 11 एससीसी 271 में रिपोर्ट की गई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम एम. टी. लट्ठी (2006) 7 एससीसी 350 में रिपोर्ट की गई, नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन बनाम नानक चंद (2004) 12 एससीसी 487 में रिपोर्ट की

गई और पंजाब नेशनल बैंक बनाम अश्विनी कुमार तनेजा (2004) 7 एससीसी 265 में रिपोर्ट की गई]।

(प) अंतिम लाभ, निवेश, पारिवारिक पेंशन सहित मासिक पारिवारिक आय और अन्य स्रोतों से परिवार की आय, अर्थात् कृषि भूमि, को प्राधिकरण द्वारा यह तय करने के लिए उचित रूप से ध्यान में रखा गया था कि परिवार गरीबी में रह रहा है या नहीं। [सोमवीर सिंह (ऊपर)]।

(फ) मृतक कर्मचारी की विधवा को पारिवारिक लाभ योजना के तहत मासिक भुगतान का आश्वासन देने वाले लाभ अनुकंपा नियुक्ति के लिए उसके रास्ते में नहीं आ सकते। पारिवारिक लाभ योजना को अनुकंपा नियुक्ति के लाभों के बराबर नहीं माना जा सकता। [बलबीर कौर बनाम सेल (2000) 6 एससीसी 493 में रिपोर्ट की गई]।

(ब) आय स्लैब का निर्धारण वास्तव में एक ऐसा उपाय है जो मनमानी के तत्व को कम करता है। जबकि, निस्संदेह, प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों को निर्णय लेने में ध्यान में रखना होगा, आय स्लैब का निर्धारण निर्णय लेने की प्रक्रिया में निष्पक्षता और एकरूपता लाने के उद्देश्य को पूरा करता है। [एचपी राज्य बनाम शशि कुमार (2019) 3 एससीसी 653 में रिपोर्ट की गई]।

(भ) अदालतें सहानुभूतिपूर्ण विचार से प्रेरित होकर लाभ प्रदान नहीं कर सकतीं [भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम आशा रामचंद्र आंबेकर (1994) 2 एससीसी 718 में रिपोर्ट की गई]।

(म) न्यायालय वैधानिक विनियमों/निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कंपनी की नियुक्ति की अनुमति नहीं दे सकते हैं। उम्मीदवार की कठिनाई उसे

ऐसे नियमों/निर्देशों के बिना नियुक्ति का हकदार नहीं बनाती [एसबीआई बनाम जसपाल कौर (2007) 9 एससीसी 571 में रिपोर्ट की गई]।

(य) नियोक्ता को उसकी नीति के विपरीत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। [केन्द्रीय विद्यालय संगठन बनाम धर्मेन्द्र शर्मा (2007) 8 एससीसी 148 में रिपोर्ट की गई]।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि उपरोक्त सभी निर्णय दो न्यायाधीशों की समन्वय पीठ द्वारा लिए गए हैं। "

7. उपरोक्त मानदंडों के आलोक में इस तथ्य के साथ कि अपीलकर्ता परिवार ने वर्ष 1991 से 1999 के बीच और आज तक परिवार में कठिनाइयों को पार कर लिया है। अतः, अपीलकर्ता ने ऐसा कोई मामला नहीं बनाया है जिससे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 26.08.2022 को सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 17804/2019 में पारित आदेशों में हस्तक्षेप किया जा सके, इस हद तक कि अपीलकर्ता कई वर्षों तक बार-बार न्यायालयों के दरवाजे खटखटाने में सोया रहा। उसे कार्रवाई का अधिकार कुछ विशेष विकासों पर आधारित था, इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश की उपरोक्त टिप्पणी हटा दी जाती है।

8. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील विलम्बित दावे के मुद्दे पर खारिज की जाती है और अनुकंपा नियुक्ति का दावा करने का कोई निहित अधिकार नहीं है।

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

(सुनील दत्ता मिश्रा, न्यायमूर्ति)

विकास/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।